

दिनांक 6.1.15

नमस्कार मित्रों ,

दो दिन बहुत ज्यादा व्यस्तता के चलते आपको कोई सूचना नहीं दे पाया उसके लिए माफी चाहता हूँ । मित्रों 3.1.15 को आप सब के सहयोग से हमने जो कुछ किया , वह आदर्श सोच में गलत हो सकता है , लेकिन यह कडवी सच्चाई है कि उँचा सुनने वालों को उँचाई पर जा कर सुनाये बिना वे सुनते नहीं , तो गलत क्या किया ? और यह सच भी साबित हुआ , जो काम हम पिछले एक तीन महीने से नहीं कर पाये वे एक दिन में हो गया । रही बात किसी साथी या हम पर मुकदमों की तो यह आम बात है लेकिन न किसी पर कार्यवाही हुई है और ना ही होगी । और उनको किसी खर्च से घबराने की जरूरत नहीं । हम करेगे सब ।

यदि ऐसे ही डरते तो हमारा देश आजाद ही नहीं होता । खैर ये विवाद का विषय हो सकता है लेकिन मैं आप सभी का जिन्होंने हमारा साथ दिया ओर जिन्होंने डर के मारे अथवा किसी अन्य कारण से हमारा साथ नहीं दिया, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा ।

दोस्तो कल की वार्ता पूर्णत : कामयाब रही । हम वास्तव में जो चाहते थे, वो ही हुआ । हम चाहते थे कि हमें कुछ संस्थाओं की तरह और नहीं समझा जावे ? इस एकट में जो विसंगतियाँ हैं उन्हे दूर किया जाये और फीस निर्धारण वाजिब तरीके से किया जाये तो हमें कोई दिक्कत नहीं । दूसरा जिन संस्थाओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी एवं पोर्टल नहीं भरा था, उन पर कार्यवाही नहीं की जावे एवं जिन संस्थाओं की फीस पोर्टल भरने अथवा नहीं भरने के कारण फीस कम हो गई है , उनकी फीस रिव्यू की जाये ।

दोस्तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अधिकारियों को कि उन्होंने न केवल सम्मानजनक तरीके से हमारी बात सुनी बल्कि हमारी तीनो बात को मान लिया एवं बहुत ही व्यवहारिक तरीके से कहा –

1. जिन संस्थाओं को कॉमन नोटिस मिला है , उनको डरने की जरूरत नहीं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा ।
2. दूसरा जिन संस्थाओं ने पोर्टल नहीं भरा एवं व्यक्तिगत नोटिस मिला है वे उसका जवाब दे देवे कि उन्होंने विसंगतियों वाले लेटर के चलते नहीं भरा । लेकिन ऐसी संस्थाओं को कहे कि जवाब जरूर देवे ।
3. जिनकी फीस पोर्टल नहीं भरने के कारण से कम हुई है और उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वे फीस रिव्यू के लिए आवेदन देवे उनके आवेदन पर विचार कर फीस में नियमानुसार बढ़ोतरी कर दी जायेगी ।

4. लेकिन जिन संस्थाओं ने 2012 मे कम फीस ले रहे थे और आरटीई के चक्कर मे ज्यादा कर दी उनको कोई राहत नहीं देगे । हम भी माफी चाहेगे उनके लिए ।
5. जहाँ तक फीस एकट मे विसंगतियों के चलते संशोधन की बात है , उसके लिए वे तैयार हैं लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि आपको पूरी तैयारी एवं सबूतों के साथ एकट के प्रत्येक प्रावधान पर क्या—क्या संशोधन चाहिए , उसका सबूत देना होगा एवं उस पर हम कार्यवाही कर आपको जवाब देगे ।
6. दोस्तों सभी चारों अधिकारियों जिनमे पी.के.गोयल साहब, प्रमुख शासन सचिव प्रारम्भिक शिक्षा, नरेश पाल गंगवार साहब, प्रमुख शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा व फीस कमेटी के सदस्य सचिव बी.आर. चौधरी साहब एवं फीस कमेटी के अनुभागाधिकारी श्री देवेन्द्र जी उपस्थित थे ।
7. हमारी तरफ से हमारी अध्यक्षा हेमलता जी, श्री शैलेश जी, श्री दिलीप मोदी जी, श्री राजेश जी शर्मा , श्री राजीव जी एवं मैं उपस्थित था ।

मेरा आप सभी साथियों से इतना सा आग्रह है कि यदि हमारे किसी साथी को नोटिस मिला हो तो उसे कहे कि अपनी वेबसाइट शिक्षापरिवार डोट कॉम से जवाब ले कर रजिस्ट्री करवा देवे एवं जिनकी फीस कम हुई है वे मैं आज कल मे एक आवेदन तैयार करूँगूँ उसमे आवेदन कर देवे मैं उनकी फीस सही करवा दूगा ।

जहाँ तक आज कल एक खबर अखबारों मे आ रही है कि फीस कमेटी 4500 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश कोर्ट से करेगी तो आप चिन्ता नहीं करे कोर्ट मे अपना वकील खड़ा है उनको जवाब देने के लिए । अपने पहले ही दो केस लगा रखे हैं ।

धन्यवाद साथियों ।  
अनिल शर्मा